

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2016

विषय: माउण्ट वैली फाउण्डेशन के नाम भवाली में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-524/12-ज्येड0ए0सी0/2015, दिनांक 31.08.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, माउण्ट वैली फाउण्डेशन नियर देवी मन्दिर भवाली जिला नैनीताल को शैक्षणिक प्रयोजन (निजी विश्वविद्यालय की स्थापना) हेतु ग्राम ल्वेशाल पट्टी पश्चिमी छ: खाता तहसील व जिला नैनीताल के खाता संख्या-93 मध्ये खसरा संख्या-2536 रकबा 1.115 है0, खसरा संख्या-2539 अ ब रकबा 1.096 है0 तथा खसरा संख्या-2540 अ ब रकबा 1.029 है0, अर्थात् कुल रकबा 3.240 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001)(संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (निजी विश्वविद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होगा।
- 3- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 5- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

9/

- 6- इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र शैक्षणिक प्रयोजन (निजी विश्वविद्यालय की स्थापना) हेतु ही किया जायेगा।
- 7- सम्बन्धित इकाई को भूमि पर निर्माण कराये जाने से पूर्व स्थल का भू-उपयोग कृषि से सामुदायिक सुविधायें (शैक्षणिक) में परिवर्तन कराना होगा।
- 8- स्थल पर निर्माण प्रचलित उप विधि के अनुसार किया जायेगा तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9- शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान सीडा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
- 10- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।
- 11- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 12- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 13- प्रश्नगत भूमि पर स्थित चीड़ प्रजाति के 410 वृक्षों का पातन/संरक्षण सम्बन्धित आवेदक इकाई द्वारा सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर तदनुरूप किया जायेगा।
- 14- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 15- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 16- सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन से पूर्व सम्बन्धित विभागों से मान्यता/अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 17- सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) से शून्य आधारित (zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 18- सम्बन्धित इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थों का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 19- सम्बन्धित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 20- जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।



21- उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की अनुपालन स्थिति से भी शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

पृ०सं०-6032 / XVIII(II) / 2016-1(45) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 5- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माउण्ट वेली फाउण्डेशन, एफ०एफ०-107 हेलिक्स राज ट्रेड सेन्टर, अपोजिट होटल सूर्या, सैयाजीगंज, बडौदा, गुजरात।
- 6- निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव।